Berhampore because it draws inspiration from a leftist political party;

(c) if so, details thereof;

(d) whether he has received representations requesting him not to shift the Headquarters and also not to withdraw recognition of the union; and

(e) if so, action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) and (e). In view of the answers for (b) & (c), (d) & (e) do not arise in so far as recognition of the employees association at Berhampore is concerned.

As regards the shifting of the Headquarters of Central Silk Board from Bombay to Bangalore, representations have been received. Although the proposal to shift the Headquarters was not considered feasible earlier due to these representations and the views of the Government of Maharashtra, after careful consideration of all aspects of the matter, have now come to the conclusion that in the long-term and over-all interest of development of Sericulture Industry in the Country, the Head quarters of the Silk Board should be shifted to Bangalore from Bombay.

छोटे समाचार पत्रों को उत्पादन शुल्क से छूट दिया जाना

1846. श्री एन. के. शेजवलकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा समाचार पत्रों पर लगाए गए 15 प्रतिशत उत्पादन-शुल्क से छोटे समाचार पत्रों को छूट दिये जाने के बारे में संसद में कोई आश्वासन दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख). देश में आयात किए जाने वाले सभी तरह के अखबारी कागजों पर, आयातकर्ताओं की श्रेणी का ध्यान रखे बिना, मूल्यानुसार सीमाशुल्क 15 प्रतिशत (10 प्रतिशत) मूल+5 प्रतिशत उपसंगी की दर से उद्ग्रहणीय है ।

वित्त मंत्री ने बित्त विधेयक पर विचार करते समय यह घोषणा की थी कि भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा विभेदी मूल्य की एक ऐसी योजना बनाई जायेगी । जिसके तहत छोटे समाचार पत्रों द्वारा आयातित अखबारी कागज पर अदा किए जाने वाले मूल्य पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा; मध्यम स्तर के समाचार पत्रों द्वारा अदा किए जाने वाले मूल्य पर केवल 5 प्रतिशत के हिसाब से आयात शुल्क लगेगा और बड़े समाचार-पत्रों द्वारा अदा किए जाने वाले मूल्य पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत समस्त शुल्क लगेगा । इस तरह से, छोटे समाचार-पत्रों को पूर्ण राहत देने और मध्यम स्तर के समाचार-पत्रों को आंशिक राहत देने का लक्ष्य बनाया गया था । राज्य व्यापार निगम ने उक्त निर्णय को लागू करते हुए 22-6-1981 को एक विभेदी मूल्य योजना की घोषणा की है ।

Probe into Gold Auction

1847. SHRI K. P. SINGH DEO:

SHRI R. R. BHOLE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the "Hindustan Times" dated 26th June, 1981 wherein the former Reserve Bank Governor who probed into gold auction cases has sought a fresh probe into the gold auction done by the Janata Government;

(b) whether it is also a fact that out of 1100 bidders all did not have enough